विचार बिन्दु

एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। –कहावत

'ट्रेड डील' या 'ट्रैप डील'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 फरवरी, 2026 को अचानक यह घोषणा कर दी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति हो गई है। उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका भारत से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर रहा है। भारत, अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर शून्य टैरिफ लगाएगा या बहुत कम कर देगा। ट्रंप की घोषणा के बाद 6 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के द्वारा एक संयुक्त विज्ञिप्त जारी की गई जिसमें ट्रेड डील के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया गया । यह उल्लेखनीय है कि पहले अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया था। चूंकि भारत द्वारा रूस से तेल आयात किया जा रहा था इसलिए उस पर 25 प्रतिशत पेनल्टी लगा दी गई थी। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका में 50 प्रतिशत की टैरिफ लागू हो गई थी ।

ट्रंप की इस एक तरफा घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समस्त भारत वासियों की ओर से अमेरिका का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की, कि इससे दोनों देशों के व्यापार को बहुत गति मिलेगी। जब से यह डील सामने आई है, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। सत्ताधारी दल, जहां इसे प्रधानमंत्री मोदी की बडी सफलता बता रहा है और इसे भारत के लिए बहुत बडी उपलब्धि बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे भारत द्वारा अमेरिका के सामने समर्पण करने जैसा बता रहे हैं। इस लेख में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है?

पाठकों की जानकारी के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 80 बिलियन डॉलर अर्थात् 7 लाख करोड़ रुपए का है। भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली वस्तुओं में विद्युत उपकरण, दवाईयां और रत्न आभूषण प्रमुख हैं। इसकी तुलना में भारत में अमेरिका से होने वाला कुल आयात 47 बिलियन डॉलर यानि 4 लाख करोड़ का है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका, आगामी पांच सालों में भारत को निर्यात 500 बिलियन डॉलर, अर्थात् 45 लाख करोड़ रुपए का करना चाहता है।

अमेरिका में भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ केवल 3 प्रतिशत का था, जिसे बढ़ा कर ट्रंप ने 50 प्रतिशत कर दिया था । अब इसी 50 प्रतिशत को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, तो इसे भारत सरकार, बडी उपलब्धि बता रही है।

प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा कार्यालय में इस उपलब्धि हेतु अभिनंदन भी किया गया। यह विचित्र बात है कि जो टैरिफ कुछ समय पहले तक 3 प्रतिशत था और उसे बढ़ाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है तो इसमें खुश होने की क्या बात है?

भारत में अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर 17 प्रतिशत का टैरिफ था जिसे अब घटाकर या तो समाप्त कर दिया जाएगा या इसे अत्यंत ही कम कर दिया जाएगा। भारत द्वारा प्रमुख रूप से सैन्य सामग्री, रेयर अर्थ मैटिरियल आदि अमेरिका से आयात किये जाते हैं। अब महंगी गाडियां, शराब आदि के साथ ही फल, प्रोसेस्ड फ्रूट ज्यूस, सोयाबीन तेल, मक्का, ज्वार के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों पर अमेरिकी सरकार द्वारा वहाँ के किसानों को बहुत बडी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। इस कारण वहां के किसानों की उत्पादन लागत बहुत कम हो जाती है। यदि भारत में इनके आयात पर लगभग शून्य टैरिफ कर दिया तो विभिन्न प्रकार के फल, प्रोसेस्ड फूड, सोया तेल, मक्का आदि पर आदि बहुत बडी मात्रा में अमेरिका से आयात होगा। चूंकि यहां पर उसकी कीमत भारतीय उत्पाद के मुकाबले में कम होगी तो भारत के लोग वहां के उत्पादों को अधिक खरीदेंगे । इसके फल स्वरुप भारत में इन वस्तुओं के उत्पादकों को बहुत बडी मार पडेगी और वह कर्ज और बेरोजगारी में डूब जाएंगे। इसमें भारत के लोगों के लिए खुश होने की क्या बात है?

यह उल्लेखनीय है कि अब तक भारत से होने वाला निर्यात अमेरिका से होने वाले आयात की तुलना में लगभग दो गुना था । अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि अगले 5 वर्ष में अमेरिका द्वारा भारत को 500 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का निर्यात किया जाएगा। वर्तमान में अमेरिका द्वारा भारत को लगभग 47 बिलियन डॉलर का निर्यात किया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में अमेरिका का आयात लगभग 10 गुना बढ़ जाएगा । जब सेव, सोया तेल और एथेनॉल बनाने के लिए मक्का अमेरिका से भारत में बहुत बडी मात्रा में आएगा तो यहां की सोया तेल बनाने वाली फैक्ट्रियां लगभग बंद होने की स्थिति में आ जाएंगी। परिणामस्वरूप, बेरोजगारी बहुत बढ़ने की संभावना रहेगी। साथ ही जब तेल फैक्ट्रियां बंद होंगी तो किसानों का सोयाबीन कौन खरीदेगा?

भारत-अमेरिका डील का विस्तृत विवरण तो मार्च के अंत में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा, किंतु अभी से जिस प्रकार का जश्न भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है और इसे भारत की जीत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है वह सही नहीं है।

इसे पारस्परिक डील का नाम दिया गया है। जब अमेरिका, टैरिफ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर रहा है और भारत 17 प्रतिशत से शून्य कर रहा है तो यह अमेरिका से भारत में वस्तुएं बड़ी संख्या में लाने का काम करेगी । इसके कारण यहां बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी । पारस्परिक समझौते का सामान्य अर्थ होता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करें। वर्तमान डील इस सिद्धांत के ठीक विपरीत है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत पर अमेरिका के दबाव के कारण हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप, मोदी या उनके मित्रों की किसी कमजोरी का लाभ उठा रहे हों। गौतम अदानी के विरुद्ध अमेरिकी न्यायालय द्वारा सम्मन एक वर्ष से अधिक समय तक भारत सरकार लेकर बैठी रही। दबाव का एक और कारण एप्सटीन फाइल में कई भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और अनिल अंबानी जैसे उद्योगपतियों के नाम आना भी संभावित हैं। यह भी जानकारी में आया है कि भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एपिस्टीन के निजी सहायक को भारत का वीसा देने के लिए सिफारिश की थी। एपस्टीन जैसे बाल यौन हिंसा में लिप्त अपराधी के साथ भारतीय मंत्रियों और उद्योगपतियों का नाम जुडना भारत सरकार के लिए अटपटी स्थिति उत्पन्न करता है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से जब रूस से तेल की खरीद बंद करने के लिए अमेरिका की शर्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि इस संबंध में कोई भी उत्तर विदेश मंत्रालय ही दे सकता है। यदि वास्तव में अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो इससे भारत को लगभग 1 लाख करोड रुपए साल का नुकसान होगा। न केवल यह, इससे यह भी सिद्ध होगा कि भारत की विदेश नीति के संबंध में निर्णय भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में लिए जा रहे हैं । भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र देश है और इसकी विदेश नीति और आर्थिक नीति किसी अन्य देश के दबाव में संचालित हो, यह भारत के स्वाभिमान के विपरीत है। यह स्थिति प्रारंभ से लेकर अब तक सभी सरकारों द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के अनुकूल नहीं है ।

भारत-अमेरिका डील का विस्तृत विवरण तो मार्च के अंत में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा, किंतु अभी से जिस प्रकार का जश्न भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है और इसे भारत की जीत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है वह सही नहीं है। यह डील के पक्ष में पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास प्रतीत हो रहा है। अमेरिका से जो खाद्य पदार्थ, तेल, फल आदि आयात होंगे, उससे यहाँ किसानों के हित पर बहुत विपरीत प्रभाव पडेगा ।

डील के बारे में स्पष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा कुछ कहा नहीं जा रहा है। बस केवल यह कहा जा रहा है कि भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। स्पष्ट रूप से किसी प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिल पा रहा है । संभव है, यदि भारत रूस से तेल खरीद रोकने पर राजी न हो तो डील ही न हो पाए।

अमेरिका की कृषि मंत्री ने इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए भारत के 150 करोड़ लोगों का बाजार खोलने वाला बताया है। इससे भारत के किसानों में आशंका उत्पन्न हुई है और अभी से विभिन्न किसान संघ इसका विरोध करके आन्दोलनात्मक रूप अपना रहे हैं। सरकार के लिए आवश्यक है कि सभी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने के लिए इस ट्रेड डील के बारे में स्पष्ट रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ नागरिकों को सारी बातें बताए। ऐसा नहीं किया जाता है तो लोगों के मन में आशंका बनी रहेगी कि यह डील अमेरिकी दबाव के समक्ष आत्म समर्पण करने का परिणाम है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा का श्रेय भी स्वयं लेने की बात अनेक बार ट्रंप ने कही थी, तब भी भारत के प्रधानमंत्री की ओर से इसका खंडन तक नहीं किया गया। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति मनमाना बयान देते रहें और हम उसका प्रतिवाद तक न करें।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत - अमेरिका डील को 'ट्रेड डील' के बजाय 'ट्रैप डील' कहना अधिक उपयुक्त होगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

जाति की राजनीति: लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करती सियासत

डॉ. नीरज रावत

समकालीन भारत एक ऐसे विरोधाभास से गुजर रहा है, जिसे नज़रअंदाज़ करना अब आसान नहीं रहा। एक ओर हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करता है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में जाति की मौजूदगी लगातार और मुखर होती जा रही है। राजनीति से लेकर प्रशासन और सामाजिक व्यवहार तक, जाति किसी न किसी रूप में निर्णायक भूमिका निभाती दिखती है। यह स्थिति केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर सवाल खडे करती है।

यह स्पष्ट है कि जाति भारतीय समाज की ऐतिहासिक सच्चाई रही है। इसे नकारना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या एक आधुनिक, संवैधानिक लोकतंत्र की राजनीति को हमेशा जातीय पहचान के इर्द-गिर्द ही संगठित होना चाहिए? क्या नागरिक की पहचान उसके अधिकारों, कर्तव्यों और क्षमताओं के बजाय जन्म आधारित श्रेणियों से तय होती रहेगी? स्वतंत्रता के बाद देश के नीति-निर्माताओं की परिकल्पना इससे अलग थी। संविधान ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान किए। इनका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना था, न कि उन्हें स्थायी राजनीतिक पहचान में बदल देना। किंतु समय के साथ यह संतुलन बिगड़ता चला गया। सुधार के लिए बनाई गई व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे सत्ता की राजनीति का हथियार बनती जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि जाति की राजनीति सशक्तिकरण से अधिक चुनावी गणित का रूप ले चुकी है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे बुनियादी मुद्दे अक्सर हाशिये पर चले जाते हैं, जबकि जातीय समीकरण चुनावी विमर्श के केंद्र में आ जाते हैं। नीतियों और योग्यता पर बहस के बजाय, समाज को छोटे-छोटे खांचों में बाँटकर समर्थन जुटाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका असर लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता पर साफ़ दिखाई देता है।

यह प्रभाव केवल चुनावों तक सीमित नहीं है। नौकरियों, पदोन्नतियों और संस्थागत निर्णयों में भी जाति का दबाव महसूस किया जाता है। परिणामस्वरूप योग्यता और दक्षता पर संदेह की स्थिति बनती है, जिससे शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। समाज में आपसी भरोसा कमजोर पड़ता है और नागरिक स्वयं को पहले किसी जाति का सदस्य और बाद में देश का नागरिक मानने लगते हैं। किसी भी आधुनिक राष्ट्र के लिए यह प्रवृत्ति घातक कही जा सकती है। विडंबना यह है कि जाति की राजनीति अंततः उन्हीं वर्गों को नुकसान पहुँचाती है, जिनके नाम पर इसे जायज़ ठहराया जाता है। लगातार 'पीड़ित' की पहचान में बाँधे जाने से आत्मनिर्भरता, उद्यम और प्रतिस्पर्धा की भावना कमजोर होती है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने चेताया था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। आज लगता है कि हम उस चेतावनी से सीखने के बजाय, सामाजिक विभाजनों को और गहरा कर रहे हैं।

राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं कि समाज एकरूप हो जाए, बल्कि यह कि सभी नागरिक कुछ साझा संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार करें। यदि राजनीति का आधार केवल जाति बनता चला गया, तो देश विभिन्न हित-समूहों का ढीला-ढाला गठजोड़ बनकर रह जाएगा। ऐसी स्थिति न तो लोकतंत्र को मजबूत करती है और न ही सामाजिक एकता को।

अब समय है गंभीर आत्ममंथन का। न्याय का अर्थ केवल संसाधनों का बँटवारा नहीं, बल्कि अवसर की समानता भी है। राजनीति को जाति की संकीर्ण भाषा से बाहर निकालकर संविधान, विकास और नागरिक अधिकारों की व्यापक समझ की ओर लौटना होगा। अन्यथा यह आशंका बनी रहेगी कि संविधान केवल एक आदर्श दस्तावेज़ बनकर रह जाएगा, जबकि उसकी आत्मा धीरे-धीरे कमजोर होती चली जाएगी।

–डॉ. नीरज रावत, लेखक जयपुर

पुस्तक समीक्षा काव्य संग्रह : "जिंदगी मुस्कुराती रहे"

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक डॉ. लीलाधर दोचानियां गध और पध दोनों के विधाओं के सशक्त हस्तक्षार है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े लीलाधर की कविताओं में साफगोई झलकती है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में पद स्थापन के दौरान उन्होंने जो देखा, अनुभव किया वही अपनी कविताओं में परोसा। काव्य कृति के रूप में उनकी यह प्रथम पुस्तक है। ॅ

ापने कविता संग्रह में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जीवन की सहज अनुभूतियों और संवेदनाओं को प्रकट करता कविता संग्रह समाज और जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करता है। विविध बुराइयों को चित्रित करती कविताएं समाज को आईना दिखती है। प्रस्तुत काव्य संग्रह में नए पुराने विषयों को बड़ी सहजता और सरलता से समेटा है। कवि की गहन सोच शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। ऐसा लगता है कविताएं उनके मन की अकुलाहट और चिंतन का साक्षात परिणाम है।

निश्चय ही रचनाओं में कवि के मन और भावनाओं को सुंदर शब्दों में आकार लिया है। कविताओं में विविध विषयों को सरल शब्दों के माध्यम से संप्रेषित कर एक अनूठा प्रयोग किया है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से सजीव रूप में परोसा गया है। कविताएं अपने व्यक्तिगत अनुभवों की श्रंखला के रूप में आकार लेती हैं साथ ही सामाजिक सच्चाइयों का संचार भी करती हैं।

113 पृष्ठ के इस कविता संग्रह में 96 काव्य रचनाएं है। पुस्तक केवल कविताओं का ही नहीं बल्कि भावनाओं, संवेदनाओं और अभिव्यक्ति का भी सशक्त संग्रह है। सभी कविताएं हृदय को छूने वाली है। आशा है कि यह कविता संग्रह पाठकों को पसंद आएगा।

समीक्षक कृति : जिंदगी मुस्कुराती रहे।
कवि : डॉ. लीलाधर दोचानियां ।
समीक्षक : बालमुकुंद ओझा

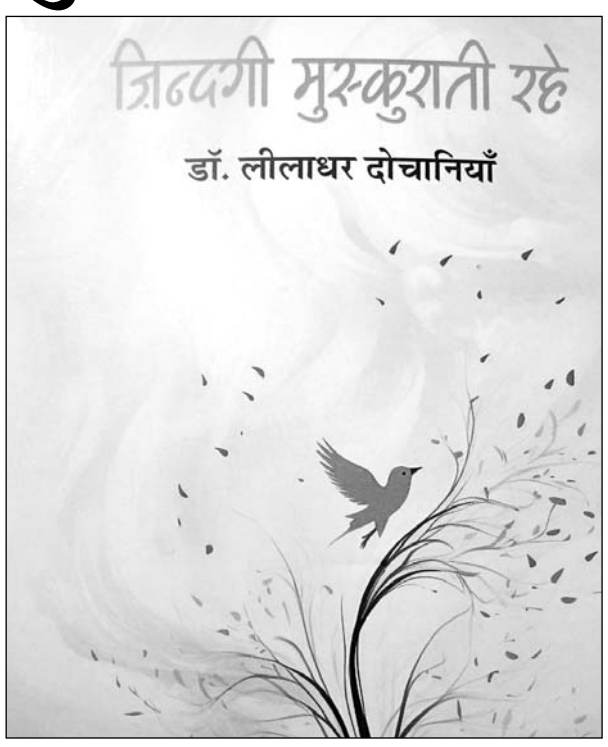

प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी का दौर शुरु

बीकानेर, (निसं)। मौसम ने करवट ले ली है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीकानेर शहर में अधिकतम तापमान अब बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके चलते दोपहर के समय गर्मी का असर महसूस होने लगा है। धूप तेज होने से लोग अब सर्द कपड़ों से राहत पा रहे हैं और दिन में हल्के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ने लगा है।

न्यूनतम तापमान में भी इजाफा दर्ज किया गया है। बीकानेर में रात का तापमान अब 15.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सुबह और देर शाम हल्की ठंड तो बनी हुई है, लेकिन सर्दी का असर पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। मौसम में यह बदलाव पिछले दो दिनों से लगातार जारी है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। किसी भी जिले में बारिश या बादल छाने की स्थिति नहीं रही। राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया, जहां पारा 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पाली में 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अलवर : सड़क हादसे में लैपर्ड की मौत

वन विभाग टीम ने मृत लैपर्ड का पोस्टमार्टम करवाया।

अलवर, (निसं)। नारायणपुर क्षेत्र के नांगलहेड़ी गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक लैपर्ड की मौत हो गई। यह हादसा नारायणपुर-कुशलगढ़ रोड पर उस समय हुआ, जब अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लैपर्ड की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लैपर्ड के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को तालवृक्ष रेंज कार्यालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों की टीम की ओर से विधिवत पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की ओर से लैपर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि लैपर्ड प्रथम श्रेणी का वन्यजीव है, जिसकी सुरक्षा को लेकर विशेष नियम लागू हैं।

वन विभाग के रेंजर त्रिलोक कुमावत ने बताया कि मृत लैपर्ड नर था और उसकी उम्र करीब ढाई वर्ष आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में लैपर्ड की मौत का कारण सड़क दुर्घटना सामने आया है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र वन्यजीवों की नियमित आवाजाही वाला इलाका है और तेज रफ्तार वाहन वन्यजीवों के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अनिल कुमार, वनपाल मनोज नागा, पशु चिकित्सक डॉ. रमेश चंद वर्मा, डॉ. मुकेश सैनी, डॉ. कमलेश सैनी सहित वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। वन अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वन क्षेत्र से गुजरते समय सतर्कता बरतें और वाहनों की गति नियंत्रित रखें, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

"बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान" की शुरुआत

एडीएम बीना महावर एवं एडिशनल एसपी कामले शरण गोपीनाथ ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अलवर, (निसं)। जन जीवन कल्याण संस्थान की ओर से जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से 100 दिवसीय "बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान" के तहत जिले में जागरूकता गतिविधियों की शुरुआत की गई। अभियान के अंतर्गत सोमवार को मिनी सचिवालय से बाल विवाह मुक्त रथ को एडीएम बीना महावर एवं एडिशनल एसपी कामले शरण गोपीनाथ ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी ओ. रविकांत साहिल एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसे रोकने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। जन जीवन कल्याण संस्थान से जुड़े लोकेश ने जानकारी दी कि यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों में जाकर बाल विवाह के खिलाफ नारे लगाएगा और आमजन को बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान की जानकारी देगा। साथ ही लोगों को कानूनी प्रावधानों और दंड के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों की सोच बदलना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान मनीषा कुमारी, पुष्पेन्द्र सहित संस्थान के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 10 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र प्रातः 7:55 तक, ध्रुव योग रात्रि 1:42 तक, कौलव करण प्रातः 7:28 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थितिः सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज अष्टमी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:56 से 11:19 तक, लाभ-अमृत 11:19 से 2:04 तक, शुभ 3:26 से 4:48 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 6:11

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

सिंह
घर-परिवार में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।